हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 02 मार्च, 2026, समय 1305 (5 मिनट)

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार राज्य का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 में हरियाणा का कुल बजट 2 लाख 25 हजार करोड़ से अधिक है।

बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा -

मुख्यमंत्री ने शुद्ध ऋण की व्याख्या करते हुए बताया कि किसी भी वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए नए ऋण तथा पिछले ऋणों के किए भुगतान के बीच के अंतर को शुद्ध ऋण कहा जाता है।उन्होंने कहा कि उत्तर एवं दक्षिणी बिजली वितरण निगमों को ब्याज के रूप में 6,200 करोड़ रुपये की बचत हुई है। अब 1,730 करोड़ रुपए का ऋण वर्ष 2036-37 में ही वापस कर दिया जाएगा।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगले वर्ष से लगातार इसका असर राज्य सरकार के शुद्ध ऋण की कमी के रूप में अवश्य ही दिखेगा। वर्ष 2014-15 में शुद्ध ऋण में 10.3% वृद्धि हुई थी। वर्ष 2024-25 में शुद्ध ऋण में यह वृद्धि गिरकर 4.91% रह गई है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह 35,457 करोड़ है, जो कि वर्ष 2036-37 के बजट में 40,148 करोड़ अनुमानित है।

मुख्यमंत्री ने बजट में हरियाणा में एक और बिजली वितरण निगम बनाने का प्रस्ताव रखा । किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन इस निगम से दिए जाएंगे।

श्री सैनी ने कहा कि एआई मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में चार विभागों से प्रस्ताव आए हैं।

****

हरियाणा ने कर प्रशासन में सुधार और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देकर राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसी कड़ी में आबकारी एवं कराधान विभाग ने सकल राज्य जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा का सकल राज्य जीएसटी संग्रह, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड 22% की दर से बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष में हरियाणा का सकल राज्य जीएसटी संग्रह, देनदारी के के बाद 44,460 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के फरवरी तक के संग्रह से 7,918 करोड़ रुपए अधिक है। इस प्रकार 22% की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है।

प्रवक्ता ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का सकल राज्य जीएसटी संग्रह राष्ट्रीय औसत 6% की दर से बढ़ा है। फरवरी माह में भी हरियाणा का सकल राज्य जीएसटी वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष के फरवरी माह की तुलना में 23% अधिक रही है। सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद द्वारा किए गए जीएसटी दर युक्तिकरण के बाद के महीनों में भी हरियाणा, राज्य जीएसटी संग्रह में लगातार स्थिर वृद्धि दिखा रहा है, जो न केवल कुशल कर प्रशासन को दर्शाता है बल्कि राज्य की स्वस्थ अर्थव्यवस्था को भी प्रतिबिंबित करता है।

****